पटरी से उतरता बाल कल्याण कार्यक्रम

मंज़ूर अली,
शोध अधिकारी
सी.बी.जी.ए, नई दिल्ली,

Published in Compact Amar Ujala,
Dated: 12 June, 2013

१२वी पञ्च वर्षीय योजना ने देश के विकाश के लिए मानव संशाधन और उसके क्षमता के उन्नति को महत्वपूर्ण माना है. यह क्षमता वृद्धि बिना स्वास्थ्य एवं पोषण के संभव नहीं है. और जिस देश के बच्चे कुपोषण और भुखमरी के शिकार हो उसकी तरक्की में निश्चित ही बाधा उत्पन्न होगी. हमारे देश की ४१ प्रतिसत आबादी बच्चों की है जिसमे ४२ प्रतिसत बच्चे कुपोषित है.

दुनिया में माँ की हालत (२०१३) नामक एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल ३ लाख ९ हज़ार बच्चे जन्म वाले दिन ही मौत के शिकार हो जाते है. रिपोर्ट यह भी जानकारी देती है की अगर भारतीय अमीर परिवार के बच्चों की तरह गरीब परिवार के नवजात शिशुओं को सुविधाएँ मिले तो ये बच्चे काल का ग्रास बनने से बच सकते है. रिपोर्ट आर्थिक असमानता की ओर इशारा कर रही है. हालाकिं, चंद सालों में यह अवधारणा बढ़ी है की गरीब कोई भी हो सकता है. यानि की जातिगत व्यवस्था वाले इस समाज में एक ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है. इस बात में कोई भी दो राय नहीं है की गरीब समाज के उच्य वर्ग से भी हो सकते है. मगर कुछ फर्क हमेशा रहेगा. मसलन, एक पिछड़े वर्ग/दलित की आर्थिक स्थिति सदियों से नहीं बदली है. वहीँ उच्य वर्ग की आर्थिक सफ़र उच-नीच से गुजरती रही है. बुरे दौर में राज्य हमेशा ही उच्य वर्ग के मदद के लिए कदम उठाते रहे है. मगर दलित की मदद इतिहास में आज तक (आज़ादी तक) किसी राज्य ने नहीं किया है. तीसरी बात, उच्य वर्ग के पास सदैव ही सामाजिक पूंजी का अम्बार रहा है जो येन-केन प्रकारेण एक दुसरे की मदद करते है. मगर, दलित की सामाजिक पूंजी इतिहास में नगण्य रही है. इसलिए गरीबी और दलित/पिछड़े वर्ग का सम्बन्ध अभी भी प्रगाढ़ है और इसलिए जब बच्चों की भुखमरी तथा कुपोषण का जिक्र हो तो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि को टटोलने की जरुरत है. सभी को एक सामान रूप से देखना थोडा अव्यवहारिक होगा.

लेकिन बाल कल्याण कार्यकर्म के सबसे बड़ी योजना एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) को बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि से दूर रख कर सभी को सामान रूप से लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है. एकीकृत बाल विकास योजना की स्वतंत्र जांच के बाद पता चला है की दलित बस्तियों में रह रहे बच्चों को इस योजना को लापरवाही से क्रियान्वित किया जा रहा है. बिहार में C.R.Y नामक स्वमसेवी संस्था ने बिहार लोक अधिकार मंच के साथ मिलकर एकीकृत बाल विकास योजना का २० जिलों में सर्वेक्षण किया और पाया की दलित और महादलित बस्तियों में 45,381 आईसीडीएस केंद्रों में से 200 को ही

सेवा प्रदान कर पा रहा है. लगभग आधे योग्य बच्चे इसके लाभ से वंचित है. सरकार के आलोचनात्मक रिपोर्ट में एकीकृत बाल विकास योजना के विफलता के बारे में वर्णन तो किया जाता है लेकिन किस वर्ग के बच्चों को ज्यादा नुकसान उठाना पद रहा है यह अस्पष्ट रह जाता है.

सच्चर कमिटी के रिपोर्ट के बाद से अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की नई १५ सूत्री कार्यक्रमों में यह बात कही गयी की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले इलाकों में उनके लिए खास प्रयोजन किया जाय. लेकिन ५-६ साल बीत जाने के बाद एकीकृत बाल विकास योजना का अल्पसंख्यक बहुल इलाके में कार्यान्वयन बहुत ही लचर रहा है. CBGA (२०१२) के एक अध्यन के मुताबिक २७,७९७ आंगनवाडी केंद्र के लक्ष्य में मुकाबले मात्र ९,९५६ केंद्र ही बनाये गए, यानि मात्र ३६ कार्य पूरा हुआ. राज्यवर आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ९,५८१ केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमे मात्र ४० प्रतिसत की कम हो पाया यानि की ३,७९८ केंद्र बन पाए. ठीक ऐसे ही बिहार में ४,८३५ केन्द्रों के लक्ष्य के सामने मात्र ४६९ केंद्र बने यानि १७ प्रतिसत. आसाम में २,०७७ के मुकाबले सिर्फ २७३ केन्द्रों का निर्माण सुनिश्चित किया गया. यह दर्शाता है की पिछड़े तबकों को लचर कार्यान्वयन से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अत: सरकार से निवेदन है की वह एकीकृत बाल विकास योजना रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के बच्चों के लाभार्थी के प्रतिसत को जरुर दर्शाए. अन्यथा, बाल विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम यूँही अपारदर्शिता बने रहेंगे. परेशानी सिर्फ लचर कार्यान्वयन का नहीं है बल्कि बहुत सारी प्रणालीगत कमजोरियों भी है. इसमें मुख्यत: है अलग-अलग राज्यों में योजना को सही ढंग से लागु करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की कमी. 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार देश भर में बाल विकास परियोजना अधिकारी की ९००६ पदों की मंजूरी है लेकिन ३४.९८ प्रतिसत यानि ३१५० पदें रिक्त है. पर्यवेक्षक की ३७.१३ प्रतिसत पदें रिक्त है तथा १९२३८८ आंगनवाडी कार्यकर्ता की पदें रिक्त है. अब ऐसे में योजना का कार्यपालन सुचारू कैसे हो सकता है. सरकार को चाहिए की जल्द से जल्द इन रिक्त पदों पर भरे. बुनियादी ढांचे, समय पर पैसे संस्था को जाना, व्यय की गुणवत्ता , उचित योजना इत्यादि प्रणाली को मजबूत करती है. इसलिए सरकार, राज्य तथा केंद्र, को इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए एकीकृत बाल विकास योजना को लागु करे. बच्चे हमारे देश के भविष्य होते है उनके समृधि के साथ लापरवाही देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा.